तिब्बती देश

तिब्बत में आत्मदाह चीनी दमन का नतीजा

गत कुछ महीनों में 23 तिब्बतियों द्वारा आत्मदाह की दुःखद घटनाओं से प्रमाणित हो जाता है कि साम्राज्यवादी चीन की सरकार के लिए तिब्बत में मानवाधिकारों की सुरक्षा का कोई मूल्य नहीं है। आत्मदाह करने वालों में बौद्ध भिक्षु–भिक्षुणी तथा बच्चे भी शामिल हैं। ऐसी दुःखद घटनायें भविष्य में नहीं घटें इस हेतु चीन सरकार पर चौतरफा प्रभावी दबाव डालने की आवश्यकता है।

चीन ने स्वतंत्र तिब्बत पर 1949 से प्रारंभ करके 1959 तक पूर्णतः अवैध कब्जा कर लिया था। इस अवधि में चीनी सेना द्वारा व्यापक पैमाने पर तिब्बतियों का कत्ल किया गया। वहाँ के बौद्ध मठ–मंदिर नष्ट किए गए तथा इतिहास एवं संस्कृति को मटियामेट किया गया। इसके बाद से लगातार चीन की सरकार तिब्बत के पूर्ण चीनीकरण की नीति पर चल रही है।

तिब्बत की धार्मिक–सांस्कृतिक विरासत की समाप्ति चीन की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। तिब्बती करूणा, मैत्री, अहिंसा तथा सहयोग–सद्भाव वाले होते हैं। वे विश्व शांति तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण–संवर्धन के पक्षधर हैं। ऐसा उनके स्वभाव में है, क्योंकि वे भगवान बुद्ध के अनुयायी है। बौद्ध ग्रंथ, मठ–मंदिर तथा शिक्षा केंद्र इन्हीं आध्यात्मिक जीवनमूल्यों के प्रचार–प्रसार में समर्पित हैं। इसलिए दमनकारी चीन सरकार ने हजारों बौद्ध अध्ययन केंद्र एवं बौद्ध उपासना स्थल तोड़ दिए। यह सिलसिला अब भी थमा नहीं है। हालत बद से बदतर होती जा रही है और तिब्बती बौद्धों को आत्मदाह करना पड़ रहा है। यह करूणा–मैत्री की हत्या है। उच्च मानवीय आध्यात्मिक मूल्यों की हत्या है। भगवान् बुद्ध के दर्शन की हत्या है। विश्व मानवता के महत्वपूर्ण तिब्बती सांस्कृतिक धरोहर का विनाश है।

तिब्बत में साजिशपूर्वक चीनियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ाई गई है कि तिब्बती ही अल्पसंख्यक हो चले। प्रशासन, उद्योग, खेती, व्यवसाय तथा महत्वपूर्ण संस्थानों पर चीनी मूल के लोगों का कब्जा हो चुका है। तिब्बती अपने ही घर में मालिक से बंधुआ मजदूर बना दिए गए। उनके सभी कार्यों पर चीनियों का नियंत्रण है। तिब्बती परिवार एवं विवाह–व्यवस्था विकृत एवं लांछित–अपमानित की जा रही है। ऐसे में अपनी दुर्दशा एवं दमन के प्रति विश्व को आकर्शित करने के लिए तिब्बती स्वयं को ही आग के हवाले कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा और न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आई.सी.जे.) समेत अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन समय–समय पर तिब्बत में जारी चीनी दमन के विरोध में कई प्रस्ताव पारित कर चुके हैं। उन प्रस्तावों में चीन सरकार की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की कठोर शब्दों में भर्त्सना की गई है। लेकिन हर बार चीन ने उन प्रस्तावों को मानने से यह कहकर इंकार कर दिया कि तिब्बत का मामला चीन का घरेलू मामला है। चीन का यह कुटिल व्यवहार संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुलेआम उल्लंघन है। चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो अधिकार प्राप्त है,जिसका वह तिब्बत के मामले में धृष्टतापूर्वक दुरूपयोग कर रहा है। विश्व संस्था को इस ओर पर्याप्त ध्यान देने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ इस मामले में तिब्बत समर्थक विश्वजनमत का साथ दे।

तिब्बती नेता एवं धर्मगुरू दलाई लामा वर्षों से तिब्बत में जारी चीनी दमन की ओर विश्व का ध्यान आकर्षिक करने में लगे हैं। विश्वसमुदाय ने उनकी बातों को पूरा महत्व भी दिया है। नोबल शांति पुरस्कार समेत उन्हें अनेक सम्मान एवं पुरस्कार दिए गए हैं। अनेक देशों के जनप्रतिनिधि चीन सरकार के विरोध के बावजूद दलाई लामा को आमंत्रित करते हैं और तिब्बत की आजादी हेतु प्रस्ताव पारित करते हैं। उन प्रस्तावों में दलाई लामा के कुशल मार्गदर्शन में जारी तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के अहिंसक एवं शांतिपूर्ण स्वरूप की प्रशंसा की जाती है।

दलाई लामा स्वयं चीनी नेतृत्व के साथ वार्ता के पक्ष में हैं। दलाई लामा के दूत 1992 से कई बार चीनी प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता कर चुके हैं। लेकिन चीन की सरकार हठधर्मी बनी हुई है। वह दलाई लामा को ही ''विघटनकारी'' बताने लगती है। स्वतंत्रता प्रेमी तिब्बती चीन से पूर्ण आजादी हेतु आंदोलन कर रहे हैं। फिर भी दलाई लामा सिर्फ वास्तविक स्वायत्तता का प्रस्ताव चीन के सामने रख चुके हैं। तिब्बत में विनाश एवं दमन से आहत दलाई लामा चाहते हैं कि चीन के अधीन रहकर भी तिब्बती मूल्यों एवं परंपराओं को पुनर्जीवित कर लिया जाए। वे सार्वजनिक रूप से कहते रहते हैं कि उनका विरोध चीन की जनता से नहीं है। उनका मत है कि तिब्बत को पूर्ण चीनीकरण से बचाने हेतु चीन के नियंत्रण में रहते हुए भी वास्तविक स्वायत्तता प्राप्त कर लेना एक उपयुक्त कदम होगा। किंतु चीन की सरकार तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता देने को भी तैयार नहीं है।

चीन द्वारा दलाई लामा को विघटनकारी बताने तथा तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता देने से भी इंकार करने एवं तिब्बत के अंदर व्यापक विनाश करने के फलस्वरूप तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के हिंसक हो जाने का खतरा मंडराने लगा है। भगवान् बुद्ध एवं महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा के आदर्शों पर चलनेवाले दलाई लामा अब राजप्रमुख का पद छोड़ चुके हैं। वे केवल धर्मगुरू रह गए हैं। विश्वभर में फैले तिब्बती प्रधानमंत्री लोबसंग संग्ये के नेतृत्व में नई सरकार का गठन कर चुके हैं।चीन में भी नया नेतृत्व आने को है।इस बीच तिब्बत में जारी आत्मदाह–आत्महत्या की घटनाओं ने विश्वभर में फैली तिब्बती युवा पीढ़ी तथा अन्य सभी तिब्बत समर्थकों के तेवर कड़े कर दिए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में संलग्न नई पीढ़ी पूर्ण आजादी चाहती है। वह तिब्बत के लिए केवल स्वायत्तता के पक्ष में नहीं है।

ऐसे में भारत की भूमिका ज्यादा बढ़ जाती है। बुद्धभूमि भारतभूमि को दलाई लामा गुरूभूमि कहते हैं। स्वयं दलाई लामा मार्च 1959 से तथा धर्मगुरू कर्मापा जनवरी 2000 से भारत में सम्मान निवास एवं प्रवास कर रहे हैं। वे तिब्बत से भागकर और भी किसी देश में शरण ले सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे भारत–तिब्बत संबंधों को महत्व देते हुए भारत आए। उस समय चीन ने उन्हें शरण देने के लिए भारत का भारी विरोध किया, लेकिन भारत ने बिना झुके उन्हें और उनके साथ आए अन्य तिब्बतियों की पूरी सहायता की। भारत की इस सहायता के लिए पूरा तिब्बती समुदाय भारत के प्रति कृतज्ञ है।

तिब्बत पर चीन का अवैध कब्जा भारत के लिए ही सबसे बड़ा संकट है। इससे भारत को सामरिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरण के क्षेत्र में काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि वह तिब्बती आंदोलन की पूरी मदद करे। विश्वस्तर पर सक्रिय होकर तिब्बत के पक्ष में मिल रहे व्यापकजनसमर्थन को सकारात्मक परिणाम में परिणत करने हेतु उपयुक्त कदम उठाए। तभी चीन के विस्तारवादी मंसूबों पर रोक लगेगी और तिब्बत में दुर्भाग्यपूर्ण आत्मदाह–आत्महत्या जैसी घटनाओं का दौर समाप्त होगा।

ik ';keukFk feJ

चीन में 12 तिब्बतियों ने खुद को आग लगाई

संगठन ने बताया कि तिब्बती जनता की वाजिब शिकायतों का गला घोंटने के लिए 'देशभक्ति शिक्षा' को थोपने और सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए यह इलाका सबसे प्रमुख बन गया है।

(रायटर्स, 2 दिसंबर)

एक पूर्व तिब्बती बौद्ध भिक्षु ने तिब्बत के पहाड़ी इलाके में खुद को आग लगा ली है, इस प्रकार वह इस साल चीन के विरोध में इस अतिवादी कदम का सहारा लेने वाला 12वें तिब्बती व्यक्ति हो गए हैं। एक विदेशी संगठन ने यह जानकारी दी है। निर्वासित तिब्बती सूत्रों के हवाले से वाशिंगटन स्थित अंतरराष्ट्रीय तिब्बत अभियान ने बताया कि तिब्बत स्वायतशासी क्षेत्र के चेंगदू प्रशासनिक क्षेत्र स्थित एक तिब्बती नागरिक तेनजिन फुंसोग ने खुद को आग लगा लिया है। यह हिमालयी पठार में आत्मदाह की पहली घटना है। संगठन ने बताया कि यह भिक्षु बच गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। तिब्बतियों के कई सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जैसे माइक्रोब्लॉग और फेसबुक पर इस घटना की जानकारी दी गई है। इस साल मार्च से अब तक अन्य 11 तिब्बती भिक्षु एवं भिक्षुणी (जिनमें कुछ पूर्व भिक्षु शामिल हैं) खुद को आग लगा चुके हैं। कहा जाता है कि इन सभी लोगों ने 76 साल के दलाई लामा को वापस बुलाने और तिब्बत की आज़ादी की मांग करते हुए ऐसा किया है। दलाई लामा 1959 से ही निर्वासन में भारत में रह रहे हैं। इनमें कम से कम छह लोग अपनी जान गवां चुके हैं। नवीनतम घटना के बारे में तिब्बत के एक सरकारी अधिकारी ने रायटर्स को बताया, "हमें इस मामले के बारे में कोई सूचना नहीं है।" चेंगदू प्रशासनिक क्षेत्र की पुलिस भी इसके बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं है, उसका कहना है कि वह पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं देती। एक सूत्र के हवाले से अंतरराष्ट्रीय तिब्बत अभियान ने बताया कि आत्मदाह का प्रयास करने वाले पूर्व भिक्षु चामदो कस्बे में स्थित कर्मा मठ से जुड़े थे। संगठन ने कहा कि अन्य सूत्रों ने बताया है कि यहां गत अक्टूबर माह में एक सरकारी इमारत में बम विस्फोट की अफवाह के बाद प्रशासन ने मठ को बंद करा दिया है। हालांकि, संगठन द्वारा दी गई सभी जानकारी की स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं की जा चुकी क्योंकि विदेशी पत्रकार बिना इजाजत के तिब्बती स्वायत्तशासी क्षेत्र में नहीं जा सकते। चीन सरकार ने इस साल अभी तक विदेशी पत्रकारों के क्षेत्र में दौरे का इंतजाम नहीं किया है। चीन सरकार अक्सर साल में एक बार इन इलाकों में विदेशी पत्रकारों का दौरा करवाती है। चीन सरकार के लिए इस तरह की विरोध प्रदर्शन की घटनाएं बहुत छोटी हैं, लेकिन ये उसकी क्षेत्रीय नीतियों के लिए चुनौती पैदा कर रही हैं जिनसे उसका दावा है कि तिब्बतियों को गरीबी और दासता से उबारा जा सका है। चीन इस इलाके में 1950 में सैनिकों के कदम रखने के बाद से ही शासन कर रहा है जिसे कि वह तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र कहता है। चीन का विदेश मंत्रालय आत्मदाह करने वालों को 'आतंकवादी' बताता है और उसने कहा है कि दलाई लामा (जिनकी चीन हिंसक अलगाववादियों के समर्थक कहकर आलोचना करता रहा है) को इस तरह के 'अनैतिक' आत्मदाह की घटनाओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ओलंपिक खेलों से पहले मार्च, 2008 में चीनी लोगों की उपस्थिति के खिलाफ समूचे तिब्बत प्रशासनिक क्षेत्र और तिब्बती क्षेत्रों में भयानक दंगे शुरू हो गए थे, जिसमें कई बार सुरक्षा बलों और पुलिस से तिब्बती लोगों की जबर्दस्त टकराव भी हुआ। तिब्बतियों के बीच पूज्यनीय दलाई लामा ने इन आत्मदाह की घटनाओं की न तो आलोचना की है और न ही नजरअंदाज किया है, बल्कि उनका कहना है कि चीन के कठोर शासन के तहत तिब्बतियों को जिस तरह की भयावह दशाओं में रहना पड़ रहा है (जिसे वह सांस्कृतिक नरसंहार कहते हैं) उससे आत्मदाह की घटनाओं को बढ़ावा मिला है। उन्होंने इस बात से इंकार किया है कि वे हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह सिर्फ अपने मातृभूमि के लिए वास्तविक स्वायत्तता चाहते हैं।

vkRenkg dk i;kl tkjh] iwohZ frCcr esa 13oha frCcrh us [kqn dks vkx yxkbZ

(तिब्बत पोस्ट इंटरनेशनल, 2 दिसंबर, धर्मशाला)

चीनी शासन के विरोध में साल 2009 से अब तक 13 तिब्बतियों ने खुद को आग लगा ली है। इनमें ज्यादातर भिक्षु या पूर्व भिक्षु हैं। इस तरह की नवीनतम घटना 1 दिसंबर, गुरुवार को हुई जब एक पूर्व बौद्ध भिक्षु ने खुद को आग लगा ली। आग की लपटों से झुलस जाने या इसके बाद चीनी पुलिस द्वारा विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए गंभीर पिटाई से ऐसी घटनाओं में कई शहीद भी हो चुके हैं। गुरुवार को आत्मदाह का प्रयास करने वाले पूर्व भिक्षु का नाम तेनजिन फुंसोक है और वह 40 साल के हैं। पूर्वी तिब्बत के कर्मा मठ के इस पूर्व भिक्षु ने चामदो में गुरुवार को खुद को आग लगा लिया और इसके बाद उन्हें चीनी पुलिस के जवान उठा ले गए। अब उनकी क्या हालत है इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उनकी पत्नी का नाम डोलमा हैं और उनके एक बेटा और एक बेटी है। गौरतलब है कि इसके पहले पिछले एक साल में धार्मिक आज़ादी, मानवाधिकारों की बहाली और तिब्बतियों के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को वापस बुलाने की मांग को लेकर 12 तिब्बतियों ने खुद को आग लगा ली है।

खबरों के अनुसार नवीनतम घटना के बाद चामदो में स्थित कर्मा मठ के भिक्षुओं के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई। अमेरिका स्थित एक मानवाधिकार संगठन ने बताया कि तिब्बत में साल 2008 में फैले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के बाद से ही चामदो में सुरक्षा प्रतिबंध बढ़ा दिए गए हैं। इसकी प्रतिक्रिया में दुनिया भर के तिब्बती और उनके समर्थक तिब्बत के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर की सरकारों पर कुछ कदम उठाने के लिए दबाव बनाने हेतु लगातार आयोजन कर रहे हैं। संगठन ने बताया कि तिब्बती जनता की वाजिब शिकायतों का गला घोंटने के लिए 'देशभक्ति शिक्षा' को थोपने और सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए यह इलाका सबसे प्रमुख बन गया है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने चीन सरकार से आग्रह किया है कि वह तिब्बतियों पर अपनी दमनकारी नीति को थोपना बंद करे और ज्यादा से ज्यादा धार्मिक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी दे। धर्मशाला स्थित तिब्बती प्रशासन ने चीन से निवेदन किया है कि उसे स्वतंत्र प्रतिनिधियों और मीडिया के लोगों को तिब्बत जाने का मौका देना चाहिए ताकि वे परिस्थिति का सही अंदाजा लगा सकें और आत्मदाह के प्रयास में घायल तिब्बतियों के उपचार के लिए डॉक्टरों के दल को वहां जाने की इजाजत देनी चाहिए। अमेरिकी एवं यूरोपीय सांसदों ने तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर गहरी चिंता जताई है और इस क्षेत्र में हाल में हुए कठोर कार्रवाई की निंदा की है। सांसदों ने आह्वान किया है कि तिब्बती जनता के बुनियादी अधिकारों और उनकी विशिष्ट संस्कृति का सम्मान करें।

yhd gbZ rLohjksa ls frCcr esa phuh cccZjrk dk [kqyklk

(फायूल डॉट कॉम, धर्मशाला 4 दिसंबर)

तिब्बत से ऐसी कई तस्वीरें लीक होकर बाहर आई हैं जिनसे तिब्बत में चीनी बर्बरता और तिब्बती भिक्षुओं एवं आम आदमी पर चीनी सुरक्षा बलों की कठोर कार्रवाई और ताकत के भद्दे प्रदर्शन को साफ तौर पर देखा जा सकता है। अमेरिका स्थित चीनी वेबसाइट बॉक्सुन डॉट कॉम ने शुक्रवार को कुछ तिब्बतियों की आठ तस्वीरें जारी की हैं जिनमें उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, उन्हें सेना की गाड़ियों में बिठाकर सार्वजनिक परेड कराई जा रही है, उनके साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा अधिकारी हैं। कुछ तस्वीरों में वे घुटनों के बल झुककर बैठे हुए हैं। उनके गले में तख्तियां लटकी हुई हैं जिन पर उनका नाम और 'अपराध', जैसे 'अलगाववादी', लिखे हुए हैं। दूसरी तस्वीरों में बड़ी संख्या में सशस्त्र जन पुलिस और सशस्त्र जन पुलिस की विशेष शाखा के जवान कंधों पर स्वचालित रायफल लटकाए सड़कों पर टहलते दिख रहे हैं। वेबसाइट में यह नहीं बताया गया है कि यह तस्वीरें किस जगह की और कब की हैं, लेकिन कई निर्वासित तिब्बतियों और संगठनों ने इन तस्वीरों को पहचान लिया है। फायूल से बात करते हुए धर्मशाला में निर्वासित लोगों के केंद्र कीर्ति मठ के एक भिक्षु कानयाग सेरिंग ने चार ऐसी तस्वीरों की पहचान कर यह बताया कि ये तस्वीरें पूर्वी तिब्बत के नाबा इलाके की हैं। सेरिंग ने फायूल को बताया, "जिस मैदान में सैकड़ों चीनी सशस्त्र सुरक्षा कर्मी बैठे दिख रहे हैं वह नाबा के कीर्ति कस्बे का सार्वजनिक बास्केटबाल ग्राउंड है। इसी तरह कार के भीतर से ली गई तस्वीर भी कीर्ति की है क्योंकि अपने सीने पर स्वचालित रायफल लटकाए चौराहे पर जो चीनी सुरक्षा बल के जवान दिख रहे हैं उनके पीछे कीर्ति मठ का स्तूप दिख रहा है।"

हालांकि सेरिंग इस बात को लेकर सुनिश्चित नहीं हैं कि यह तस्वीर कब खींची गई होगी। उन्होंने दो अन्य तस्वीरों में भी मकानों एवं सड़कों की पहचान कर ली है जिसमें सशस्त्र सैनिक मार्च करते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। सेरिंग ने बताया, "वह तस्वीर जिसमें हरे और नीली वर्दी में चीनी सुरक्षा बलों के जवान दिख रहे हैं वह नाबा शहर अदालत के पास ली गई है।" गौरतलब है कि साल 2011 के मार्च में कीर्ति मठ के एक युवा भिक्षु फुंसोग द्वारा चीनी कब्जे के विरोध और दलाई लामा को निर्वासन से वापस बुलाने की मांग को लेकर आत्मदाह कर लेने के बाद से ही नाबा के कीर्ति मठ और उसके आसपास के इलाकों में प्रशासनिक प्रतिबंध बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके बाद से 11 और तिब्बतियों ने खुद को आग लगा ली है जिसमें भिक्षु, भिक्षुणी और आम लोग शामिल हैं। इसमें नवीनतम घटना 1 दिसंबर को चामदो में हुई जहां तेनजिन फुंसोक ने खुद को आग लगा ली। मार्च के बाद से पहली बार नाबा जाकर रिपोर्टिंग करने में सफल रहे एएफपी के रिपोर्टर रॉबर्ट सैगेत ने अक्टूबर में लिखा था, "पुलिस के पास बहुत से दंगा निरोधक ढाल हैं और वे बंदूक एवं लोहे की रॉड के साथ सड़कों पर कतारबद्ध रूप से तैनात हैं।" एएफपी की रिपोर्ट हाल में लीक हुई तस्वीरों की पुष्टि करती है। इसमें कहा गया है, "स्वचालित रायफलें, लोहे के नोकीले रॉड और अग्निशमन यंत्र लिए सादी वर्दी वाले सैनिकों का बड़ा समूह घूम रहा है, जबकि पुलिस की बसों, ट्रकों और सशस्त्र जवानों के वाहनों ने सड़कों को बंद कर रखा है।" फेसबुक पर बीजिंग की पुरस्कृत तिब्बती ब्लॉगर और आंदोलनकारी वुएजर ने लिखा है कि वह इन तस्वीरों को देखकर दहल गई हैं। वुएजर ने लिखा है, "इन तस्वीरों से साफ पता

भारत से हम केवल चीन का धन और सैन्य ताकत ही देख पा रहे हैं। हम यह नहीं देख पा रहे कि हर साल विरोध प्रदर्शन की 80,000 घटनाएं हो रही हैं जिसका काफी बर्बरता से दमन किया जा रहा है।

चलता है कि तिब्बतियों के सच को दबाया जा रहा है।

'एक शरणार्थी के रूप में यहां रहते हुए भारत की बढ़ती ताकत को देखना आश्वस्त करने वाला': सुनडु

(टाइम्स ऑफ इंडिया, 16 दिसंबर, 2011)

"चीन पश्चिम में रह रहे तिब्बतियों से नहीं डरता बल्कि भारत और नेपाल में रह रहे तिब्बतियों से डरता है क्योंकि भारत एवं नेपाल की सीमा चीन से मिलती है। इसलिए तिब्बतियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे भारत या नेपाल में रहें।"

तिब्बती कवि और आंदोलनकारी तेनजिन सुनडु साल 2002 में तब चर्चा में आए थे, जब चीनी प्रधानमंत्री झू रोंगजी की भारत यात्रा के दौरान उन्होंने मुंबई के ओबेरॉय टावर की 14वीं मंजिल पर चढ़ कर तिब्बती झंडा फहराया था, जहां झू भारतीय कारोबारी दिग्गजों को संबोधित कर रहे थे। अपने भावुक लेखन के लिए प्रख्यात आंदोलनकारी सुनडु को भारत के सबसे स्टाइलिश लोगों में माना जाता है। सुनडु ने हाल के वैश्विक बौद्ध सम्मेलन (जो कि विवादित हो गया), बौद्ध भिक्षुओं के खुद को आग लगाने और दलाई लामा के राजनीति से सन्यास लेने के बाद तिब्बत आंदोलन पर क्या असर पड़ा है, इसके बारे में अमरदीप बनर्जी से बात की।

gky d of"od ck) lEeyu dk phu dh vkykpuk dk f"kdkj gkuk iMk vkj lkQ rkj ij phu dh vkifRr dk n[kr g, gh jk'Vifr ifrHkk ikfVy vkj i/kkueU=h euekgu flg ble "kkfey ugh g,A vkidk D;k ekuuk g

यह गर्व की बात है कि बौद्ध समागम आयोजित करने और इसके समापन समारोह का मुख्य अतिथि दलाई लामा को बनाए जाने के मामले में भारत अडिग रहा। साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक के दौर के विपरीत इस बार चीन के दबाव में न झुकने के प्रति भारत सरकार ने ज्यादा आत्मविश्वास दिखाया। यहां एक शरणार्थी के रूप में हमें भारत की बढ़ती ताकत काफी आश्वस्त करने वाली लगती है।

yfdu cgr ykx vk"oLr ugh g] fiNy ,d lky e 10 l T;knk frCcfr;k u vkRenkg dk i;kl fd;k gA D;k vkidk yxrk g fd vkRenkg fojk/k dju dk o/kkfud rjhdk g

साल 2008 की जनक्रांति के बाद से ही चीन सरकार तिब्बत पर नियंत्रण को लेकर असुरक्षा की भावना से ग्रस्त है। तिब्बत में अंतरराष्ट्रीय मीडिया और पर्यटक मुक्त रूप से घूम–फिर नहीं सकते, लोगों की आवाजाही को भी सीमित कर दिया गया है। क्रूर पुलिसिया शासन में तिब्बती घुटन महसूस कर रहे हैं जिसकी वजह से वे आत्मदाह करने को मजबूर हो रहे हैं। चीनी पुलिस की बर्बरता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने और आज़ादी की मांग करने का यह चरम कदम है। भारत में (खुली हवा में) रहते हुए मुझे इसकी वैधानिकता पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

nykbl ykek d jktuhfr l lU;kl yu l frCcrh vknkyu ij D;k vlj iMk g

दलाई लामा द्वारा राजनीतिक अधिकार चुने हुए नेतृत्व को हस्तांतरित करने को एक त्याग के कदम के रूप में ही देखना चाहिए। दलाई लामा के इस निर्णय से तिब्बती जनता अपना ऐसा नेतृत्व चुनने में सक्षम हुई है जो सभी तरह के राजनीतिक मामलों में पूरी तरह जवाबदेह हो। यह हमारा चीनी दुष्प्रचार को जवाब है जो यह कहते हैं कि निर्वासित तिब्बती समुदाय पुराने सामंती समाज को फिर से खड़ा करना चाहता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि हमने पिछले 50 साल से लोकतंत्र के साथ सफलतापूर्वक प्रयोग कर रहे हैं।

ektnk phu&Hkkjr lc/kk dk vki fdl :i e n[kr g

चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जे के बाद भारत–चीन के बीच संबंधों को जो दांव पिछले 60 साल से चल रहा है उसमें ज्यादातर डर और संदेह का ही वातावरण रहा है। अब इसे आर्थिक प्रतिस्पर्धा और अनुपयुक्त राजनय के रूप में देखा जा सकता है। प्रमुख मसलों में से एक 4,057 किलोमीटर लंबी सीमा है। अरुणाचल प्रदेश पर भारत का दावा 1914 के मैकमोहन समझौते पर आधारित है, जबकि चीन इस समझौते को नहीं मानता। दोनों देशों का बुनियादी रवैया भिन्न है, इसलिए जल्दी किसी समाधान की उम्मीद नहीं दिखती। आज भारत दबाव में है क्योंकि चीन ने तिब्बत में विशालकाय सैन्य निर्माण कर लिया है, उसके पास हिमालय से निकलने वाली नदियों का नियंत्रण है और चीन पड़ोसी देश पाकिस्तान का करीबी है। वैमनस्य की वजह से ही दोनों देश हिमालय के दोनों तरफ का सैन्यीकरण कर रहे हैं, जब तक तिब्बत को एक बफर क्षेत्र के रूप में बहाल नहीं किया जाता भारत और चीन के बीच हमेशा शीतयुद्ध जारी रहेगा।

yfdu D;k vkidk ^vktkn frCcr^ dh ekx 0;kogkfjd yxrh g

भारत से हम केवल चीन का धन और सैन्य ताकत ही देख पा रहे हैं। हम यह नहीं देख पा रहे कि हर साल विरोध प्रदर्शन की 80,000 घटनाएं हो रही हैं जिसका काफी बर्बरता से दमन किया जा रहा है। और यह सब भयावह होता जा रहा है, इतना ज्यादा कि हाल में दलाई लामा ने यह आकलन किया कि चीन का आंतरिक सुरक्षा बजट उसके प्रतिरक्षा बजट

से भी ज्यादा हो गया है। इसका मतलब यह है कि बाहर से ज्यादा घर में उनके शत्रु हैं। इन पर नियंत्रण करने की उनकी जिद से देश टूटकर बिखराव के कगार पर जा रहा है।

lLdfr lj{k.k d ,d fo"kky lxk'Bh e Hkkjr; fo}kuk u frcr ij ppk dh

(तिब्बत डॉट नेट, 1 दिसंबर, धर्मशाला)

पटना में आयोजित एक विशाल संगोष्ठी में कई भारतीय विद्वानों और हस्तियों ने तिब्बत समस्या के हल होने के भारत पर सकारात्मक असर की चर्चा की। इसमें धार्मिक एवं राजनीतिक जगत के लोग भी शामिल थे।

संस्कृति गौरव संस्था द्वारा स्थानीय ए.एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट फॉर सोशल स्टडीज में आयोजित इस संगोष्ठी के दौरान "स्वतंत्र तिब्बतः भारत के लिए वरदान" विषय पर भी चर्चा हुई। इस दो दिवसीय संगोष्ठी के अंतिम सत्र में 30 नवंबर को तिब्बती प्रशासन के गृह विभाग की मंत्री कालोन ट्रिपा डोलमा ग्यारी ने भारत एवं तिब्बत के हजारों साल पुराने धार्मिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के महत्व पर प्रकाश डाला। कालोन ग्यारी डोलमा ने इस बात का महत्व बताया कि परमपावन दलाई उसी प्राचीन भारतीय नालंदा परंपरा से जुड़े हैं जिसके आधार पर तिब्बत में सातवीं शताब्दी से ही बौद्ध परंपरा फल–फूल रही है। तिब्बत की पहचान को बनाए रखने में भारत के समर्थन को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने भारत से आह्वान किया कि भारत एवं तिब्बत के बीच धार्मिक एवं सांस्कृतिक जोड़ बनाए रखने के लिए लगातार समर्थन देता रहे। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए दिल्ली स्थित भारत–तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक तेनजिन नोर्बू ने भारत–तिब्बत के बीच हजारों साल पुराने संपर्क को संरक्षित रखने पर जोर दिया। इस संपर्क को जीवंत और मजबूत बनाए रखने पर जोर देते हुए श्री नोर्बू ने कहा कि मौजूदा तिब्बती संस्कृति जो संकट चल रहा है उससे भारत के भी अपनी प्राचीन परंपरा को खो देने का खतरा है। इसके बाद तिब्बत डॉट नेट से बात करते हुए श्री नोर्बू ने बताया कि संगोष्ठी में शामिल होने वाले लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की भलाई के लिए तिब्बत का अस्तित्व में रहना अपरिहार्य है। उन्होंने कहा, "वक्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत–चीन के बीच राजनीतिक रूप से एक बफर देश के रूप में तिब्बत की स्थिति खत्म होते ही 1962 के भारत–चीन युद्ध जैसी विनाशक घटनाएं हुईं और चीन एवं भारत में अब भी सीमा विवाद जारी है।" उन्होंने कहा, "वक्ताओं ने इस बात पर भी चर्चा की कि तिब्बत का पठार का महत्व उस समूचे एशिया के लिए जीवनरेखा की तरह है जो अपने जल के लिए वहां से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर निर्भर हैं।" उन्होंने कहा, "वक्ताओं का यह मानना था कि तिब्बत के आंदोलन को समर्थन करना हर भारतीय की जिम्मेदारी है।" नोर्बू ने कहा कि इस संगोष्ठी के दौरान मुंबई, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और जम्मू–कश्मीर के कई नए भारतीय समर्थक तिब्बत आंदोलन से जुड़े। इस संगोष्ठी में महेश समीर, प्रोफेसर पारस राय, प्रोफेसर अर्जुन सिंह, दिनेश चंद्र त्यागी, प्रोफेसर ललित गुप्ता, प्रख्यात पत्रकार विजय क्रांति और अन्य कई प्रमुख विद्वानों ने हिस्सा लिया।

इनके अलावा धार्मिक एवं राजनीतिक जगत से जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी, भाजपा नेता उमा भारती, विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंहल, जगतगुरू शंकराचार्य, विजय सोनकर शास्त्री और कई पूर्व सांसद इस संगोष्ठी में शामिल हुए। इस संगोष्ठी के दौरान जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई उनमें भारतीय संस्कृति के विकास का तरीका, भ्रष्टाचार से निपटने का तरीका, लोकपाल कानून को कैसे लागू किया जाए, चीन की अवनतिकारक नीति और भारतीय पर्यावरण की रक्षा आदि रहे।

"मैं हमेशा भारतीय रहूंगा। तिब्बतियों को ज्यादा कल्पनाशील और ज्यादा सृजनशील बनना होगा।"

निर्वासित तिब्बती नेताओं ने चीन पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया

(द चाइना पोस्ट, 11 दिसंबर, धर्मशाला)

निर्वासित तिब्बती समुदाय के राजनीतिक नेताओं ने आरोप लगाया है कि चीन तिब्बत में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है जिसकी वजह से आज़ादी की मांग करने वाले तिब्बती 'हताशा' भरे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। यहां शनिवार को दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर तिब्बती नेताओं ने यह बात कही। गौरतलब है कि इस साल कम से कम 12 तिब्बती भिक्षु, भिक्षुणी और पूर्व भिक्षु खुद को आग लगा चुके हैं। ऐसी ज्यादातर घटनाएं चीन के सिचुआन प्रांत में हुई हैं। इन्हें तिब्बती जीवन और संस्कृति पर बढ़ते सख्त चीनी नियंत्रण की वजह से हो रही हताशा की कार्रवाई माना जा रहा है। निर्वासित तिब्बती समुदाय कें केंद्र धर्मशाला में प्रधानमंत्री लोबसांग सेंगे ने कहा, "तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति इतना ज्यादा खराब हुई है कि तिब्बतियों को चरम और अभूतपूर्व कार्यों का सहारा लेना पड़ रहा है। अपने अध्यात्मिक नेता परमपावन दलाई लामा को साल 1989 में नोबेल सम्मान मिलने के दिन 10 दिसंबर को तिब्बती समुदाय वार्षिक समारोह के रूप में मनाता है। इस दिन

उन्होंने कहा कि भारत को इसी प्रकार भविष्य में भी चीन से सख्ती से निपटना चाहिए।

अमेरिका के इस निर्णय से तब चीन काफी नाराज हुआ था।

धर्मशाला के सुगलांगखांग मंदिर में सैकड़ों तिब्बती एक सभा में शामिल हुए। तिब्बत मसले का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए प्रतिबद्धता को देखते हुए परमपावन दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हालांकि, इस शनिवार को स्वयं दलाई लामा चेक रिपब्लिक के पूर्व राष्ट्रपति वाक्लाव हावेल के एक निमंत्रण पर प्राग में थे। सभा को संबोधित करते हुए सेंगे ने कहा, "चीन सरकार से यह हम कहना चाहते हैं कि तिब्बत में असल शांति और स्थिरता लाने का एक मात्र रास्ता यह है कि तिब्बती जनता के बुनियादी मानव अधिकारों का सम्मान किया जाए।" इस अवसर पर तिब्बती कलाकारों ने बैगपाइपर बजाए।

तिब्बत में मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर यूरोपीय संसद ने कार्रवाई का आह्वान किया

(एनटीडी न्यूज, 5 दिसंबर, ब्रसेल्स)

अपने जवाब में गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि वे दलाई लामा को वीजा देने से इनकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पास इस मामले में निर्णय लेने का 'समय नहीं था।'

गत 29 नवंबर, मंगलवार को ब्रसेल्स स्थित यूरोपीय संघ ने एक सम्मेलन आयोजित कर तिब्बत की स्थिति की जानकारी दी। इस सम्मेलन में यूरोपीय संसद के कई सांसद, मानवाधिकार संगठनों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल हुए और उन्होंने तिब्बत में हो रही मानवाधिकार उल्लंघन और लगातार जारी आत्मदाह की गंभीर घटनाओं पर प्रकाश डाला। भारत स्थित निर्वासित तिब्बती प्रशासन के प्रधानमंत्री डॉ. लोबसांग सेंगे पहली बार ब्रसेल्स आए। यहां हम सभी वक्ताओं के भाषण के मुख्य अंश दे रहे हैं।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कालोन ट्रिपा डॉ. लोबसांग सेंगे ने कहा, "यह सिर्फ एक नहीं 12 आत्मदाह के मामले हैं। इसलिए मैंने अमेरिका का दौरा किया और अब मैं यूरोपीय देशों का दौरा कर रहा हूं इन सरकारों से अनुरोध करने के लिए कि वे बयान जारी करें और मौत के मुंह में जा रहे तिब्बती जनता का साथ दें। इस तरह के बयान तिब्बत के भीतर रहने वाले तिब्बतियों में आशा की किरण जगाएंगे।"

अमेरिकी विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने बयान जारी किए हैं और कुछ यूरोपीय देशों ने भी बयान जारी किए हैं।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कालोन ट्रिपा डॉ. लोबसांग सेंगे ने कहा, "निश्चित रूप से और आखिरकार इसके लिए चीन सरकार और उसकी दमनकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। हमें इसका समाधान करना होगा। चीन सरकार की कठोर नीतियां खत्म होनी चाहिए और तिब्बत के मसले पर नए सिरे से विचार होना चाहिए। साथ ही, इससे निपटने के लिए एक संयत, शांतिपूर्ण और अहिंसक रास्ता निकालना होगा।"

यूरोपीय संसद के तिब्बत इंटरग्रुप के अध्यक्ष और तिब्बत पर सांसदों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के सह अध्यक्ष थॉमस मैन कहते हैं, "इसलिए हम सबने यूरोपीय आयोग को एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत दिया कि वह अत्यंत सक्रिय हो और जब भी यूरोपीय संघ एवं चीन के बीच कोई वार्ता हो तो उन्हें इन सवालों का जवाब उसी समय लेना चाहिए। उन्होंने ऐसा किया भी है।

गत 27 अक्टूबर को यूरोपीय संघ ने एक मानवाधिकार प्रस्ताव पारित किया जिसमें तिब्बती मठों पर चीन सरकार की कठोर कार्रवाई की निंदा की गई।

fo}kuk u fudV Hkfo';e frCcfr;k dk vkj ukt d ifjfLFkfr gku dh prkouh nh

(फायूल डॉट कॉम, धर्मशाला, 22 दिसंबर)

चीन–भारत के संबंधों के विशेषज्ञ और तिब्बत पर कई सख्त लेख लिखने वाले दिब्येश आनंद ने भारत में रहने वाले तिब्बतियों को चेतावनी दी है कि उन्हें भविष्य में और नाजुक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत के धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बतियों के मुख्यालय में कुछ खास लोगों को संबोधित करते हुए लंदन की वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर आनंद ने कहा कि दलाई लामा के निधन के बाद भारत में रहने वाले तिब्बतियों को ज्यादा अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। आनंद ने कहा, "परमपावन दलाई लामा भारत में अतिथि हैं और दलाई लामा की वजह से तिब्बती भी भारत में अतिथि हैं। लेकिन एक बार जब दलाई लामा हमारे साथ नहीं रहेंगे, भारत यह आतिथ्य–सत्कार कभी भी छीन सकता है।" यह संकेत देते हुए कि भारत सरकार द्वारा तिब्बतियों की औपचारिक पहचान किए बिना आवास प्रमाणपत्र (आरसी) जारी करना एक तरह का 'आधिकारिक युक्ति' है ताकि तिब्बत मसले को इस्तेमाल करते हुए चीन के साथ 'बेहतर कारोबार' किया जा सके, आनंद ने कहा कि तिब्बतियों को भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहिए। आनंद ने कहा, "नागरिकता कुछ नहीं बल्कि एक कागज का टुकड़ा है। इससे कुछ नहीं बदलता। यह सिर्फ सुविधा के लिए होता है। मेरे पास ब्रिटेन की नागरिकता है, इसलिए मेरे लिए कहीं भी, यहां तक कि पाकिस्तान जाना भी आसान है। लेकिन इससे भारत के साथ मेरे खून के रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आने वाला। मैं हमेशा भारतीय रहूंगा। तिब्बतियों को ज्यादा कल्पनाशील और ज्यादा सृजनशील बनना होगा।" आनंद ने हाल के अपने एक आलेख में तर्क दिया था कि निर्वासित तिब्बती नेतृत्व मध्यम मार्ग नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और तिब्बतियों के

संघर्ष की वास्तविक स्थिति (जिसमें पिछले एक साल में ही आत्मदाह के 12 मामले सामने आए हैं) के बीच बनी खाई को दूर करना चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर आनंद ने तिब्बतियों को यह भी चेतावनी दी कि अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, यूरोप या अन्य देशों में तिब्बतियों के आव्रजन की बढ़ती संख्या से आगे चलकर तिब्बती आंदोलन को संकट हो सकता है। आनंद ने जोर देकर कहा, "चीन पश्चिम में रह रहे तिब्बतियों से नहीं डरता बल्कि भारत और नेपाल में रह रहे तिब्बतियों से डरता है क्योंकि भारत एवं नेपाल की सीमा चीन से मिलती है। इसलिए तिब्बतियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे भारत या नेपाल में रहें।" तिब्बत की अपनी पहले की गई यात्रा को याद करते हुए आनंद ने कहा, "तिब्बत में बुनियादी ढांचे का विकास साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन वहां तिब्बती लोगों की गरिमा का सम्मान नहीं किया जा रहा है।"

nykbl ykek dk cjykus e ^phu dh ifrfØ;k l Mjk nf{k.k vÝhdk

(फायूल डॉट कॉम, 5 दिसंबर, धर्मशाला)

पिछले अक्टूबर माह में दलाई लामा के वीजा आवेदन को खारिज कर देने वाले दक्षिण अफ्रीका के गृह मंत्रालय ने पहली बार खुले तौर पर यह स्वीकार किया है कि दलाई लामा को दौरे की इजाजत देने में उसे चीन की प्रतिक्रिया का डर था। न्यायालय में जमा किए गए अपने बयान में मंत्रालय ने यह भी कहा है कि निकट भविष्य में भी दलाई लामा को दक्षिण अफ्रीका आने का वीजा नहीं दिया जा सकता। गौरतलब है कि निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को हाल में वीजा न मिलने के कारण दक्षिण अफ्रीका का दौरा रद करना पड़ा था। दलाई लामा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डेसमंड टुटु के 80वें जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने उनका वीजा आवेदन काफी दिनों तक लटकाए रहने के बाद आखिर में वीजा देने से इनकार कर दिया। गत 2 दिसंबर को जारी बयान में इनकाथा फ्रीडम पार्टी (आईएफपी) के सांसद प्रिंस मैंगोसुथु बुथेलेजी और मोसियोआ लेकोटा ने कहा कि सरकार द्वारा दलाई लामा को वीजा देने से इनकार करने को 'गैरकानूनी एवं असंवैधानिक' घोषित करने के लिए हाईकोर्ट में अपना जवाबी हलफनामा दे दिया है। अपने जवाबी हलफनामे में माननीय लेकोटा और बुथेलजी ने साबित किया है कि किस प्रकार इस प्रकार का आचरण कानून एवं शिष्टाचार दोनों के खिलाफ है। गृह मामलों के महानिदेशक खुसेली अपलेनी ने कहा था कि विभाग को चीन के साथ दक्षिण अफ्रीका के संबंधों और दलाई लामा के वीजा आवेदन से हमारे विदेश एवं व्यापार संबंधों पर क्या असर पड़ता', इस बात का ध्यान रखना था। अलपेनी ने यह भी याद दिलाया कि चीन ने दक्षिण अफ्रीका के दूरसंचार एंव खनन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश कर रखा है।

अपने जवाब में गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि वे दलाई लामा को वीजा देने से इनकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पास इस मामले में निर्णय लेने का 'समय नहीं था।'

इस पर आईएफपी के नेताओं ने कहा कि दलाई लामा ने सरकारी प्रक्रिया के तहत वीजा के लिए सही समय से आवेदन कर दिया था। अपने जवाबी हलफनामें में आईएफपी के नेताओं ने कहा, "सच तो यह है कि दलाई लामा ने अपनी यात्रा से चार महीने पहले ही आवेदन करना चाहा था लेकिन तब उनसे कहा गया कि वह बहुत पहले आवेदन कर रहे हैं और उन्हें दो माह बाद आना चाहिए। इसलिए उन्होंने फिर दो माह बाद आवेदन किया। यह सब दलाई लामा के बारे में दुनिया भर में और दक्षिण अफ्रीका में सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को जानने के बावजूद किया गया। अब मार्च में दलाई लामा की यात्रा के लिए वीजा देने पर सरकार को मजबूर करने के लिए मंगलवार को फिर सुनवाई होगी।

भारत सरकार को अपना विरोध जताने के लिए चीनी दूत को बुलाना चाहिए। चीन के बढ़ते अहंकार से भारत की भावना को चोट पहुंच रही है।

चीन ने भारत के कई हिस्सों पर अवैध कब्जा कर रखा हैः उमर अब्दुल्ला

(फायूल डॉट कॉम, धर्मशाला, 5 दिसंबर)

भारत के सबसे संभावनाशील युवा नेताओं में से एक और भारत–तिब्बत सीमा पर स्थित राज्य जम्मू–कश्मीर के मुख्यंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत सरकार के हाल के इस निर्णय का समर्थन किया है कि दलाई लामा के मामले में चीन के दबाव के आगे नहीं झुका जाएगा। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में शनिवार की शाम को आयोजित एक कार्यक्रम में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह दलाई लामा से कई बार मिले हैं। उन्होंने कहा कि भारत को इसी प्रकार भविष्य में भी चीन से सख्ती से निपटना चाहिए। राजनीतिक हस्तियों, वरिष्ठ कारोबारियों और सिनेमा एवं थिएटर जगत की हस्तियों को संबोधित करते हुए कहा, "हाल की एक घटना में सरकार उठ खड़ी हुई और उसने कहा कि वह दिल्ली में दलाई लामा का कार्यक्रम सिर्फ इसलिए रदद नहीं कर सकती क्योंकि चीनी अधिकारी सीमा वार्ता करने दिल्ली आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी बार–बार हो। मैं चाहता हूं कि चीन के साथ निपटने

भारत सरकार को अपना विरोध जताने के लिए चीनी दूत को बुलाना चाहिए।

(1)

(2)

(10)

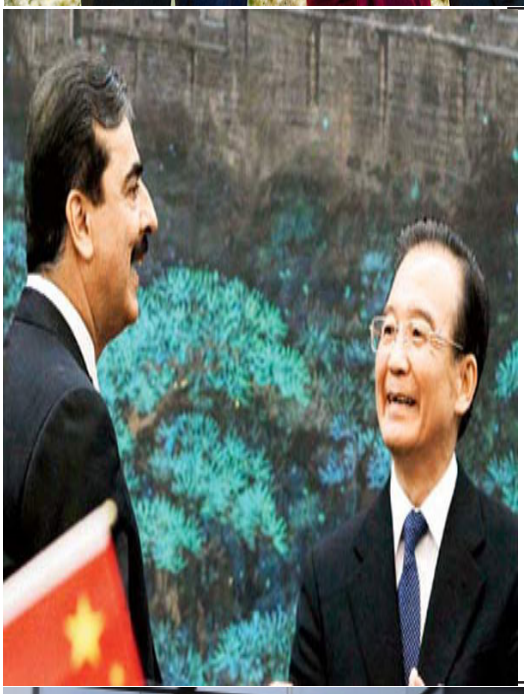

कैमरे की

1 नई दिल्ली में 2 दिसंबर, 2011 को कला, संस्कृति और शिक्षा के
2 तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा शनिवार, 10 दिसंबर, 2011
देते हुए। (एपी)
3 हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम कुमार धूमल के साथ गृह विभा
सोनम तेनफेल।
4 तिब्बत के दाओफू (ताउ) में सड़क पर जलतीं हुईं बौद्ध भिक्षुणी पा
गई और इसे 22 नवंबर को रायटर्स द्वारा जारी किया गया।
5 27 फरवरी 2009 तिब्बत के उत्तरी क्षेत्र नाबा में ज़मीन पर पडे टा
6 धर्मशााला के लाकपा सेरिंग हॉल में 20 दिसंबर, 2011 को दिब्येश
7 दक्षिण चीन में भ्रष्ट अधिकारियों और जमीन हड़पने के विरोध में वु
8 नई दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस के दिन प्रदर्शित की जा
9 एक मॉल में 'चीन में बने सामान का बहिष्कार करें' के नारे वा
10 चीन क्षेत्रीय प्रभुत्व जमाने के लिए पाकिस्तान को एक सीढ़ी की त

(9)

(8)

(3)

(4)

(5)

आंख से

लिए दयावती मोदी अवॉर्ड हासिल करते परमपावन दलाई लामा।
को प्राग में चेक के पूर्व राष्ट्रपति वाक्लाव हावेल से मुलाकात के वक्त उन्हें तोहफा

ग की कालोन डोलमा ग्यारी और निर्वासित तिब्बती संसद के डिप्टी स्पीकर खेनपो

लदेन छोएत्सो। गत 3 नवंबर, 2011 को लिए एक वीडियो शॉट से यह तस्वीर ली

बे को चीनी सुरक्षा बलों ने घेरा।
आनंद (बाएं) और कालोन डिकी छोयांग (दाएं)
कान के निवासी विरोध प्रदर्शन करते हुए। (फोटोः एएफपी–गेट्टी इमेज)
रही अग्नि मिसाइल।
ले बैनर प्रदर्शित करे आरटीवाईसी और एसएफटी मिनेसोटा के आंदोलनकारी।
रह इस्तेमाल कर रहा है।

¼QkVk ifjp; ½ Åij ck,¡ ls ?kMh dh fn'kk e½

(7)

(6)

सूत्रों ने कहा कि यदि राज्य सरकारें केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की मदद से आंतरिक स्थितियों पर काबू पा लें तो सैन्य कर्मियों को देश पर होने वाले बाह्य आक्रमण की किसी भी आशंका से बचाने में लगाया जा सकता है।

में भारत अपनी रीढ़ सीधी रखे।" इस मसले पर दलाई लामा को भारत के सभी राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है चाहे वे किसी भी विचारधारा से क्यों न जुड़े हों। भारतीय इलाके में चीन के घुसपैठ और सीमा के उस पार युद्ध स्तर पर सैन्य निर्माण कार्य करने पर चिंता जताते हुए जब तक चीन भारत की संप्रुभता पर सवाल खड़े करते रहेगा, उसे भारत से 'एक चीन नीति' पर जोर देने का आग्रह करने का कोई अधिकार नहीं है।" सत्तारूढ़ यूपीए का हिस्सा उमर अब्दुल्ला ने कहा,"वे अरुणाचल प्रदेश की स्थिति को लेकर सवाल क्यों उठाते हैं? वे जम्मू–कश्मीर के कुछ हिस्सों के बारे में सवाल क्यों उठाते हैं? उन्होंने मेरे राज्य के कुछ हिस्सों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उन्हें यह बात स्वीकार करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि काफी समय से हम पाकिस्तान और चीन के साथ अपने रिश्तों में क्षमायाचक जैसे रहे हैं और अब ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें चीन के साथ निपटने में अपने को कमतर नहीं समझना चाहिए।" उनके इस साहसी भाषण को खूब तालियां मिलीं। निर्वासित तिब्बती नेता के समर्थन में सामाजिक एवं वैचारिक खेमों से इतर भारत के सभी तरह के राजनीतिक दल आगे आए हैं।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रियन चीन की सलाह के विपरीत खुद जाकर दलाई लामा से मिले। भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भाजपा देश के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए चीन पर काफी कुपित हुई और उसने कहा कि इसके खिलाफ चीनी दूतावास के बाहर एक विरोध प्रदर्शन किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता एवं सांसद तरुण विजय ने जोर देकर कहा कि चीन की पश्चिम बंगाल सरकार को यह सलाह कि वह दलाई लामा का स्वागत न करे और उनके कार्यक्रम में शामिल न हो, किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा, ""हम इसे अपने राष्ट्रीय मामलों में सीधे हस्तक्षेप मानते हुए इसकी आलोचना करते हैं। भारत सरकार को अपना विरोध जताने के लिए चीनी दूत को बुलाना चाहिए। चीन के बढ़ते अहंकार से भारत की भावना को चोट पहुंच रही है।

Ihek ij phuh xfrfof/k;ka ij Hkkjr dh xgjh utj

(आईबीएनलाइव डॉट इन, 2 दिसंबर, नई दिल्ली)

अभी भारत और चीन को सीमा वार्ता के अगले दौर की तिथि तय करनी है, लेकिन इस बीच गुरुवार को सरकार ने कहा है कि वह सीमावर्ती क्षेत्र में चीन द्वारा बुनियादी ढांचा विकास कार्यों को तेज करने पर 'गहरी नजर' बनाए हुए है। विदेश राज्य मंत्री ई. अहमद ने संसद में एक लिखित सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। चीन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में क्विंघई–तिब्बत रेल लाइन, सड़क और एयरपोर्ट सुविधाओं के विकास का जिक्र करते हुए अहमद ने कहा, "सरकार उन सभी विकास गतिविधियों पर गहरी नजर रखे हुए है जिनका असर भारत की सुरक्षा पर पड़ सकता है और देश की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।"

अहमद ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार अपने आर्थिक एवं सामरिक हितों की रक्षा के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर सावधानी से और विशेष ध्यान दे रही है। चीन द्वारा सीमा के मसले पर नए तरह की आक्रामकता को देखते हुए भारत ने इस बात को दुहराया है कि अरुणाचल प्रदेश और जम्मू–कश्मीर भारत के अभिन्न हिस्से हैं। अहमद इस बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे कि चीन ने अपना जो नया नक्शा तैयार किया है उसमें अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया गया है। अहमद ने कहा कि चीन पूर्वी सेक्टर में दोनों देशों की सीमा रेखा पर विवाद खड़ा करता रहा है और वह अरुणाचल प्रदेश की 90 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है। गौरतलब है कि भारत एवं चीन के प्रतिनिधियों के बीच 28 व 29 नवंबर को सीमा वार्ता होनी थी, लेकिन नई दिल्ली में उसी समय एक बौद्ध सम्मेलन में दलाई लामा के शामिल होने को लेकर चीन ने आपत्ति की जिसके बाद बने मतभेद से यह वार्ता टाल दी गई। दलाई लामा को 'अलगाववादी' बताने वाले चीन ने भारत सरकार से कहा कि ठीक वार्ता के दिनों में दलाई लामा के दिल्ली में आने पर रोक लगाए, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि चूंकि दलाई लामा एक धार्मिक कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं, इसलिए उन्हें नहीं रोका जा सकता।

Pkhu lhek ij lU; rkdr c<k jgk gS Hkkjr

(असम ट्रिब्यून, गुवाहाटी, 7 दिसंबर)

भारत सरकार ने आखिरकार चीन से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा को ज्यादा महत्व देने की तात्कालिक जरूरत को स्वीकार कर लिया है और सेना की संख्या बढ़ाने और बुनियादी ढांचा विकास जैसे कार्य शुरू किए गए हैं। हालांकि, सीमा पर बुनियादी ढांचा निर्माण के मामले में चीन अब भी भारत से काफी आगे है। नई दिल्ली स्थित उच्च पदस्थ सूत्रों ने 'दि असम ट्रिब्यून' को बताया कि भारत सरकार अब चीन से लगने वाली सीमा को सुरक्षित बनाने को लेकर गंभीर है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत अब किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बेहतर रूप से

तैयार है। सीमा के आसपास होने वाले कुछ निर्माण कार्यों का उदाहरण देते हुए सूत्रों ने बताया कि भारतीय थल सेना के 3 कॉर्प्स और 4 कॉर्प्स में एक–एक नए डिवीजन बनाए गए हैं, हालांकि इन डिवीजन का मुख्यालय कहां होगा अभी यह तय नहीं हो पाया है। सूत्रों ने बताया कि सेना के 3 एवं 4 कॉर्प्स के अलावा 33 कॉर्प्स को भी पूर्वी सीमा की रक्षा में लगाया गया है। लेकिन समस्या यह है कि बड़ी संख्या में सैन्य कर्मी खासकर 3 एवं 4 कॉर्प्स के जवान आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। सूत्रों ने कहा कि यदि राज्य सरकारें केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की मदद से आंतरिक स्थितियों पर काबू पा लें तो सैन्य कर्मियों को देश पर होने वाले बाह्य आक्रमण की किसी भी आशंका से बचाने में लगाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने चीन सीमा के आसपास बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर फंड झोका है ताकि किसी भी आपात स्थिति में सैनिकों की आवाजाही को आसान बनाया जा सके। ब्रह्मपुत्र पर बन रहे बोगीबील पुल के तैयार होने से भी सेना को भारी मदद मिलेगी। सूत्रों ने बताया कि सेना नदियों से होकर जलमार्ग का विकास भी करना चाहती है ताकि इस रास्ते भी लोगों या सामान को पहुंचाया जा सके। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दुर्गम इलाकों में सैन्य कर्मियों के लिए स्थायी आश्रय बनाए जा रहे हैं, अरुणाचल स्काउट की एक बटालियन तैयार की गई है और जल्दी ही नए जवान ड्यूटी पर तैनात किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार अरुणाचल स्काउट के जवान इस इलाके की बेहतर जानकारी रखते हैं और इससे भारतीय सेना को काफी मदद मिलेगी जैसा कि लद्दाख स्काउट्स के जवानों से सेना को मदद मिली है। अरुणाचल स्काउट्स के सदस्य सेना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सीमा सड़क संगठन और आईटीबीपी के जवानों की संख्या भी बढ़ाई गई है। हालांकि, सूत्रों ने यह स्वीकार किया है कि बुनियादी ढांचा विकास की गति अब भी चीन के मुकाबले नहीं है। चीन सरकार अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पिछले कई साल से बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है, जबकि भारत ने हाल में इस सेक्टर पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया है। बुनियादी ढांचा विकास के पीछे चीन का मुख्य उद्देश्य यह है कि तेज विकास के द्वारा तिब्बत के मुख्य भूमि में समावेश को सुनिश्चित किया जा सके और उसी बुनियादी ढांचे को किसी आपदा स्थिति में सैनिकों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि, सूत्रों के अनुसार एक सकारात्मक संकेत यह है कि दोनों देशों की सेना में संबंध काफी सुधरे हैं और छोटे–मोटे विवादों को फ्लैग मीटिंग के दौरान ही सुलझा लिया जाता है।

'युद्ध के लिए तैयार रहें', चीन के राष्ट्रपति ने नौसेना से कहा

(फायूल डॉट कॉम, धर्मशाला, 7 दिसंबर)

चीनी और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की बीजिंग में वार्ता शुरू होने से एक दिन पूर्व चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ ने अपनी नौसेना से कहा है कि वह आधुनिकीकरण को तेज करे और युद्ध के लिए तैयार रहे। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ के अनुसार राष्ट्रपति हू ने जन मुक्ति नौसेना की पार्टी कांग्रेस का संचालन करते हुए सैन्य अधिकारियों से कहा कि, "राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और विश्व शांति में अपना ज्यादा योगदान देने के लिए युद्ध के लिए तैयारी बढ़ा दें।"

कई प्रेक्षकों का मानना है कि चीन के राष्ट्रपति की यह सपाट टिप्पणी उनके अक्सर किए जाने वाले इस दावे के बिल्कुल विपरीत है कि चीन 'शांतिपूर्ण रूप से उभर रहा है।' अमेरिका और चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच बुधवार को होने वाली एक दिवसीय वार्ता दोनों देशों में सितंबर के बाद हो रही पहली मंत्रिस्तरीय वार्ता है, जब वाशिंगटन ने ताइवान के एफ–16 लड़ाकू विमानों के बेड़े को बढ़ाने के लिए 5.85 अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की थी। अमेरिका के इस निर्णय से तब चीन काफी नाराज हुआ था। चीन की नौसेना ने हाल में पहला विमानवाहन जहाज हासिल किया है और वह विवादित दक्षिण चीन सागर में सक्रिय हो गई है जिसे लेकर हाल में राजनीतिक तनाव बढ़ा है। अमेरिका ने पिछले महीने उत्तरी आस्ट्रेलिया में अपना पूर्ण समुद्री कार्यबल तैनात करने की घोषणा की है, जबकि चीन के पड़ोसी देश जैसे वियतनाम और फिलीपींस (जो कि दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर अपनी प्रभुसत्ता का दावा करते हैं) लगातार चीन पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि वह इस इलाके में साफ तौर पर आक्रामकता दिखा रहा है। चीन के राष्ट्रपति हू की इस टिप्पणी के आने के कुछ दिनों पहले ही चीनी नौसेना के उच्चाधिकारियों का यह बयान सामने आया था कि ईरान के लिए चीन तीसरे विश्व युद्ध का जोखिम लेने को तैयार है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने 4 दिसंबर को चीन के रीयर एडमिरल और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय के मिलिट्री लॉजिस्टिक एवं इक्विपमेंट विभाग के निदेशक झांग झाओझोंग को यह कहते हुए बताया है कि, "तीसरे विश्वयुद्ध की नौबत आ जाए तो भी ईरान को बचाने में चीन हिचक नहीं दिखाएगा।"

भारत में रॉकेट एवं मिसाइलों का इस्तेमाल 18वीं शताब्दी से महान शासक हैदर अली और टिपू सुल्तान के जमाने से हो रहा है। वे बड़े युद्धों में पैदल सेना के खिलाफ रॉकेट तोपखाना बिग्रेड का इस्तेमाल करते थे।

दूसरी तरफ, भारत के प्रतिरक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी ने कहा है कि दक्षिण–पश्चिम हिंद महासागर में अन्वेषण कार्य के लिए चीन के आगे बढ़ने की घोषणा के बीच भारत अपनी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और कारोबारी हितों पर गहरी नजर रखे हुए है। इस मसले पर भारतीय संसद में जताई गई चिंता का समाधान करते हुए एंटोनी ने कहा, "सरकार अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और कारोबारी हितों से जुड़ी सभी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसी भी उत्पन्न स्थिति एवं सामरिक जरूरतों के मुताबिक इन हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

अग्नि–4 से भारत नई पीढ़ी की मिसाइल पथ पर आगे बढ़ा

अनिल भट

(दि एशियन एज, 16 दिसंबर, 2011)

लेकिन अहमद मंजिल की समूची सुविधा को 1975 में कंचनबाग के निकट ले जाया गया। इसके बाद से ही समुचित पैमाने की मिसाइल प्रयोगशाला (डीआरडीएल) को तैयार किया गया।

गत 15 नवंबर, 2011 को अग्नि–4 मिसाइल का उड़ीसा तट के पास व्हीलर्स द्वीप से सफलतापूर्व परीक्षण किया गया। यह भारत के मिसाइल कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण घटना है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा जारी बयान में बताया गया है कि सबसे आधुनिक दीर्घ परास वाले मिसाइल को सुबह नौ बजे रोड मोबाइल सिस्टम से प्रक्षेपित किया गया। यह अपने मार्ग पर सही तरीके से जाता हुआ करीब 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा और बंगाल की खाड़ी में पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर गिरा। इसकी सभी प्रणाली सुचारु रूप से चल रही थीं और पुनर्प्रवेश तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। इस मिशन के सभी लक्ष्य पूरी तरह से हासिल किए गए। डीआरडीओ के अनुसार यह मिसाइल अपने तरह का अनूठा है। इसमें पहली बार कई नई तकनीक का प्रदर्शन किया गया है और इससे मिसाइल तकनीक के मामले में भारत ने लंबी छलांग लगाई है। यह मिसाइल वजन में हल्का है और इसमें ठोस प्रणोदन (प्रोपल्सन) के दो चरण और री एंट्री हीट शील्ड के साथ एक पेलोड है। इसमें पहली बार इस्तेमाल किए गए कंपोजिट रॉकेट मोटर तकनीक का भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। यह मिसाइल तकनीक उच्च स्तर का भरोसा प्रदान करने के लिए आधुनिक एवं छोटे वैमानिकी सुविधा से लैस है। अतिरिक्त मोड में एक–दूसरे के पूरक बनने वाले स्वदेशी रिंग लेजर जिरोस आधारित एक्यूरेसी आईएनएस (रिन्स) और माइक्रो नेविगेशन सिस्टम (मिंग्स) ने पहली बार सफलतापूवर्क गाइडेंस मोड में उड़ान भरे हैं। वितरित विमानकी वास्तु के साथ उच्च प्रदर्शन वाला ऑनबोर्ड कंप्यूटर, उच्च गति वाला भरोसेमंद संचार बस और एक पूर्ण डिजिटल नियंत्रण वाली व्यवस्था ने मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचाया है। यह मिसाइल अत्यधिक उच्च स्तर की परिशुद्धता के साथ लक्ष्य तक पहुंचा है। उड़ीसा के तट पर लगाए गए रडार और इलेक्ट्रो–ऑप्टिकल सिस्टम ने मिसाइल के सभी पैरामीटर की निगरानी की और उस पर नजर रखा। लक्ष्य के पास नियुक्त भारतीय नौसेना के दो जहाज भी इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी बने। रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी ने डीआरडीओ टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। इस प्रक्षेपण को देख रहे रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार, प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के महानिदेशक डॉ. विजय कुमार सारस्वत ने अग्नि–4 के सफल प्रक्षेपण पर डीआरडीओ के सभी वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों और सेना को बधाई दी। इस प्रक्षेपण के बाद वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए प्रख्यात वैज्ञानिक, डीआरडीओ के मुख्य नियंत्रक (मिसाइल एवं सामरिक प्रणाली) और अग्नि के कार्यक्रम निदेशक श्री अविनाश चंदर ने इसे भारत के दीर्घ परास वाले आधुनिक नेविगेशन सिस्टम में नए युग की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा, "इस परीक्षण ने अब अग्नि–5 अभियान की सफलता का मार्ग प्रशस्त किया है, जिसे कि जल्दी ही प्रक्षेपित किया जाएगा।"

अपनी टीम के साथ मिसाइल सिस्टम तैयार करने और एकीकृत करने वाले अग्नि–4 की परियोजना निदेशक तेसी थॉमस ने काफी उत्साहित होकर कहा कि डीआरडीओ ने अग्नि प्रणाली में कई नई अत्याधुनिक तकनीक का विकास किया है और उसे सिद्ध किया है। उन्होंने कंपोजिट रॉकेट मोटरों, उच्च परिशुद्धता वाले रिंग लेजर जिरो आधारित जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली, माइक्रो नेविगेशन प्रणाली, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम और अत्यंत ताकतवर ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम की भूमिका को रेखांकित किया। सामरिक अस्त्रों को ढोने में सक्षम अग्नि–4 का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा और इसे जल्द से जल्द सेना को सौंप दिया जाएगा। यह मिसाइल बाह्य आक्रमणों का अच्छी तरह से जवाब दे सकता है। भारत में रॉकेट एवं मिसाइलों का इस्तेमाल 18वीं शताब्दी से महान शासक हैदर अली और टिपू सुल्तान के जमाने से हो रहा है। वे बड़े युद्धों में पैदल सेना के खिलाफ रॉकेट तोपखाना बिग्रेड का इस्तेमाल करते थे। सैनिकों को एक प्रक्षेपण कोण से रॉकेट प्रक्षेपित करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। इस कोण की गणना सिलिंडर के व्यास और लक्ष्य की दूरी के आधार पर की जाती थी। इन रॉकेट लॉन्चर में धमाके साथ ही एक साथ 5 से 10 रॉकेट प्रक्षेपित करने की क्षमता होती थी। टीपू सुल्तान की सेना में 27 ब्रिगेड थे और हर ब्रिगेड

में रॉकेट विशेषज्ञों की एक कंपनी होती थी। इस विशाल सेना के साथ ही उन्होंने 1799 में श्रीरंगपट्टनम में अपनी मौत होने तक मैसूर राज को अंग्रेजों से बचाकर रखा। यहीं नहीं, 1761 के पानीपत के युद्ध में मराठा सैनिकों ने भी रॉकेट का इस्तेमाल किया था। लेकिन टीपू सुल्तान की मौत के साथ ही भारतीय रॉकेट व्यवस्था की भी मौत हो गई। इसे काफी समय बाद 1970 के दशक में डॉ. विक्रम साराभाई और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के द्वारा पुनर्जीवन हासिल हुआ। ब्रिटिश सैनिकों द्वारा श्रीरंगपट्टनम में पकड़े गए दो रॉकेट को लंदन के शाही तोपखाना संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। भविष्य के हथियारों की प्रणाली पर अध्ययन शुरू करने और विकास कार्य के लिए 1956 में रक्षा विज्ञान संगठन की स्थापना की गई। इसका अध्यक्ष डॉ. बी.एन. सिंह को बनाया गया जिन्होंने निर्देशित मिसाइलों के अध्ययन एवं विकास के लिए दिल्ली के मेटकाफ हाउस में विशेष हथियार विकास दल (एसडब्ल्यूडीटी) का गठन किया। उन्होंने इस बारे में कार्य अनुभव हासिल करने के लिए पहली पीढ़ी के एंटी टैंक मिसाइल (एटीएम) पर काम किया। बाद में एसब्ल्यूडीटी का नाम बदलकर रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (डीआरडीएल) कर दिया गया और जून 1962 में इसका मुख्यालय हैदराबाद के ओल्ड अहमद मंजिल में रखा गया। ग्रुप कैप्टन वी. गणेशन को इसका निदेशक बनाया गया।

डीआरडीएल में 1964 में तैयार एक परियोजना को 1965 में भारत–पाक युद्ध के बाद सेना का भी समर्थन मिला और बाद में इसे 'स्टाफ परियोजना' में बदल दिया गया जिसने 1970 में स्वदेश में विकसित एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया। यह डीआरडीएल के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इसका मुख्यालय बाद में पुराने हैदराबाद शहर के बाहरी इलाके में स्थित कंचनबाग के रक्षा अनुसंधान परिसर में ले जाया गया। इसके बाद थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के सहयोग से कुछ वैज्ञानिकों ने डेविल मिसाइल का विकास किया। डेविल मिसाइल के इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम की सभी प्रारंभिक समझ एवं विकास जैसे एयरफ्रेम एवं एयरोडायनामिक्स आदि को अहमद मंजिल की प्रयोगशाला में किया गया था।

बर्मन, जे.सी. भट्टाचार्य, एडमिरल मोहन और सूर्यकांत राव जैसे प्रमुख वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक्स, नेविगेशन, गाइडेंस एवं कंट्रोल और टेलीमेट्री एवं इंस्ट्रुमेंशन क्षेत्र पर जोर दिया। डॉ. रंगा राव, डॉ. रामा राव, डॉ. बाला कृष्णन, कृष्णन और डॉ. अच्युतन ने एयरफ्रेम, ढांचे, एयरोडायनामिक और सिस्टम संबंधित क्षेत्रों पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) डॉ. वी.जे. सुंदरम, लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) स्वामिनाथन और स्क्वाड्रन लीडर शाह के तकनीकी–प्रबंधन कौशल वाले नेतृत्व ने एयरफ्रेम कंट्रोल और इंटीग्रेशन को और मजबूत किया। प्रणोदन आधारित डिजाइन और परीक्षणों के लिए रॉकेट परीक्षण गृह (आरटीएच, फिलहाल यह कंचनबाग के पास है) की पहचान की गई। डॉ. गोपाल स्वामी और विंग कमांडर सेन के उत्साही नेतृत्व में तरल एवं ठोस प्रणोदन कार्य जारी रहे। री एंट्री तकनीक और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व आर.एन. अग्रवाल ने किया। पी. बैनर्जी द्वारा परिसर के भीतर ही अत्याधुनिक जिरो परीक्षण सुविधा की शुरुआत की गई। लेकिन अहमद मंजिल की समूची सुविधा को 1975 में कंचनबाग के निकट ले जाया गया। इसके बाद से ही समुचित पैमाने की मिसाइल प्रयोगशाला (डीआरडीएल) को तैयार किया गया। रक्षा मंत्रालय के तहत 1980 के दशक की शुरुआत में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (आईजीएमडीपी) की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य माध्यमिक रेंज वाले अग्नि मिसाइल (सतह से सतह) और छोटी रेंज वाले मिसाइल जैसे पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल (सतह से सतह), पृथ्वी मिसाइल के नौसेना संस्करण सागरिका, आकाश मिसाइल (सतह से वायु), एस्ट्रा मिसाइल (वायु से वायु), त्रिशूल मिसाइल (सतह से वायु), नाग मिसाइल (एंटी टैंक) और 8 हजार से 12 हजार किलोमीटर तक मारक क्षमता वाले अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (कूट नाम–सूर्य मिसाइल) का विकास करना है। इस कार्यक्रम का प्रबंधन भारत सरकार के अन्य प्रयोगशालाओं एवं अनुसंधान केंद्रों के साथ मिलकर डीआरडीओ द्वारा किया जाता है। इस परियोजना से जुड़े सबसे प्रख्यात मुख्य अभियंता डॉ. अब्दुल कलाम रहे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। इस कार्यक्रम के तहत अंतिम विकसित सबसे बड़ा मिसाइल अग्नि–3 था जो माध्यमिक मारक रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका 9 जुलाई, 2007 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। अग्नि–3 के 7 मई, 2008 को तीसरे परीक्षण के बाद डीआरडीओ ने आईजीएमडीपी के बंद होने की घोषणा कर दी क्योंकि इस कार्यक्रम के तहत ज्यादातर मिसाइल का विकास कर लिया गया था और उन्हें भारतीय सेना में शामिल भी कर लिया गया था। इनमें आकाश, नाग, पृथ्वी, त्रिशूल और अग्नि शामिल हैं।

डीआरडीएल के पूर्व निदेशक और फिलहाल पुणे स्थित डीफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर डॉ. एस. प्रहलाद के मीडिया में जारी बयान के अनुसार अब नए पंचवर्षीय कार्यक्रम के तहत नए मिसाइल एवं हथियार प्रणाली का विकास किया जाएगा। इसमें लागत को कम करने के लिए

करीब 290 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाले क्रूज मिसाइल के चौथे रेजीमेंट से तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र तक भारत की सैन्य पहुंच बढ़ेगी और चीन द्वारा अपनी सीमा में तैनात मिसाइलों का मुकाबला किया जा सकेगा।

> *पत्रकार और 'चाइनीज लेशंस' के लेखक जॉन पॉमफ्रेट ने शंघाई में एक सम्मेलन में कहा, "उत्तर कोरिया–दक्षिण कोरिया के विसैन्यीकृत क्षेत्र के बाद चीन–भारत सीमा एशिया की दूसरी सबसे खतरनाक सीमा है।*

निजी क्षेत्र और विदेशी साझेदारों का भी सहयोग लिया जाएगा। नाग मिसाइल के और विकास कार्य को स्वतंत्र तौर पर जारी रखते हुए डीआरडीओ अपने बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के तहत एक लेजर आधारित हथियार सिस्टम का विकास कर रहा है जिससे भारत की धरती की ओर लक्ष्य कर दागे गए मिसाइलों को बीच में ही रोका जा सकेगा और उन्हें नष्ट किया जा सकेगा। भारत सरकार ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस (ब्रह्मपुत्र और मॉस्को नदी के आधार पर नाम) के डिजाइन, विकास, उत्पादन और बिक्री के लिए साल 1922 रूस के साथ एक समझौता किया था। इस सुपर सोनिक मिसाइल को पनडुब्बियों, जहाजों, वायुयान या जमीन से दागा जा सकता है। यह मिशन साल 2006 में सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। यह 2.5 से 2.8 मैक की गति के साथ दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है और अमेरिका के हार्पून क्रूज मिसाइल से भी साढ़े तीन गुना ज्यादा तेज है। अब ब्रह्मोस के 8 मैक गति वाले हाइपरसोनिक वर्जन ब्रह्मोस 2 के विकास का प्रयास किया जा रहा है। दुनिया का यह पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल साल 2012–13 तक तैयार हो सकता है। इंटरनेट से हासिल जानकारी के अनुसार अब तक तीन ब्रह्मोस मिसाइल रेजीमेंट पाकिस्तानी खतरे से निपटने के लिए पश्चिम में तैनात किए गए हैं और इसे दूसरे चरण में चीन सीमा पर तैनात किया जाना है। खबरों के अनुसार भारत सरकार ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की अरुणाचल प्रदेश में तैनाती को मंजूरी दे दी है। करीब 290 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाले क्रूज मिसाइल के चौथे रेजीमेंट से तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र तक भारत की सैन्य पहुंच बढ़ेगी और चीन द्वारा अपनी सीमा में तैनात मिसाइलों का मुकाबला किया जा सकेगा। गत 6 दिसंबर, 2011 को स्वदेशी तौर पर विकसित इंडियन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम (एईडब्ल्यूएंडसी) के लिए पहले पूरी तरह परिकृष्त वायुयान ने ब्राजील के साओ जोस डोस कैंपोस स्थित एम्बारेर परिसर से उड़ान भरी। भारत के लिए विकसित ईएमबी 145 (एईडब्ल्यूएंडसी) प्लेटफॉर्म में करीब 1,000 मिशन सिस्टम कंपोनेन्ट हैं जिसे बेंगलुरु के सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम ऑफ द डिफेंस रिसर्च एवं विकास संगठन (कैब्स, डीआरडीओ) ने तैयार किया है। इसमें महत्वपूर्ण एईएसए (एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग एंटेना) रडार एंटेना भी शामिल है जिसे अंतरराष्ट्रीय एफएआर प्रमाणन एजेंसी एएनडीएसी का प्रमाणनहासिल है। यह एजेंसी नागरिक विमानों एवं उसके उपकरणों, लाइसेंसिंग, संचालन और एयरोड्रम से संबंधित सुरक्षा मानकों के नियमन के लिए जिम्मेदार है। इस विमान को अगले दो साल में पूर्ण प्रमाणन प्रक्रिया से गुजरना है, इस बीच साल 2012 के मध्य तक भारतीय वायु सेना ऐसे दो विमान और साल 2013 तक कई डीआरडीओ प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित मिशन सिस्टम हासिल करेगी।

(नई दिल्ली में रहने वाले लेखक एक रिटायर्ड सेना अधिकारी और प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा विश्लेषक हैं)

Hkkjr&phu lca/kksa esa fQj vkbZ vlgtrk

(लॉस एंजेलिस टाइम्स, 18 दिसंबर, दिल्ली)

पिछले कई सालों से कुशलता से प्रबंधित हो रहे भारत–चीन संबंधों में एक बार फिर दबाव आता दिख रहा है। जानकारों के अनुसार इसकी वजह दोनों तरफ अंसवेदनशीला और राष्ट्रवाद को माना जा सकता है, एक तरफ भारत के अति सक्रिय टीवी चैनल हैं तो दूसरी तरफ चीनी मंत्रियों की बढ़ती स्वायत्तता। हाल में भारत–चीन के बीच करीब 2500 मील की विवादित सीमा पर कई अतिक्रमण की घटनाओं से उपजी खीज ने इन दो एशियाई ताकतों के बीच अविश्वास बढ़ाया है। ऐसे ही एक मामले में वियतनाम से चले एक भारतीय युद्धपोत को जुलाई माह में चीनी नौसेना का रेडियो संदेश मिला कि वह 'चीनी जल सीमा' छोड़ दें। एक और स्थिति ने भारत का मूड बिगाड़ दिया जब नवंबर में नई दिल्ली में एक चीनी मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ब्रोशर बांटा गया उसमें भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर के एक हिस्से (जिस पर भारत दावा करता है) को चीन का हिस्सा बताया गया। इस संवाददाता सम्मेलन में चीन की एक भारी उपकरण निर्माता कंपनी द्वारा भारत में 40 करोड़ डॉलर के निवेश की घोषणा की जानी थी। दोनों पड़ोसी देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं हैं, लेकिन चीनी नियोजन, बुनियादी ढांचा और वहां तेज विदेशी निवेश प्रवाह से ऐसा लगता है कि वैश्विक कारोबार मंच पर चीन दौड़ में भारत से आगे निकल गया है।

दिसंबर की शुरुआत में शंघाई में एक साझा एजेंडा गोलमेज सम्मेलन में हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के सामरिक मामलों के संपादक प्रमित पाल चौधुरी ने कहा, "इन घटनाओं पर गहरी नजर डालने से पता चलता है कि भारतीय प्रेस ने इन्हें थोड़ा बढ़ा–चढ़ा कर दिखाया है। लेकिन उन्होंने भारतीय जनता में संदेह को बढ़ाने में योगदान किया है।" कुछ साल पहले कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए चीन द्वारा पासपोर्ट से अलग कागज पर वीजा देने पर बहुत से भारतीय नाराज हुए थे। विभाजित कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान दोनों अपना दावा करते हैं और दोनों पक्षों का इसके कुछ हिस्से पर नियंत्रण है। चीन की इस वीजा नीति से यह संकेत देने का प्रयास किया

गया कि भारत के नियंत्रण वाला कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा नहीं है, जिससे बहुत से भारतीयों को कष्ट पहुंचा। इसके बाद जैसे को तैसा जैसा व्यवहार करते हुए भारत सरकार ने साल 2009 में दलाई लामा को चीन सीमा के नजदीक एक मठ की यात्रा करने की इजाजत दी। बीजिंग तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता जो 1959 में निर्वासित होकर भारत आ गए थे और अब उत्तरी भारत में रहते हैं। हाल में तिब्बत में विरोध प्रदर्शन करने वाले भिक्षुओं के आत्मदाह और तिब्बत एवं अन्य क्षेत्रों में अशांति के लिए चीन दलाई लामा को ही जिम्मेदार ठहराता है।

Hkkjr dk tokc Ni ugh ldrk: यदि आप कश्मीर पर हमारे दावे पर सवाल उठाना शुरू करेंगे तो हम आपके तिब्बत पर दावे के साथ ऐसा ही करेंगे। पिछले महीने चीन दोनों देशों के बीच होने वाली संयुक्त वार्ता से पीछे हट गया क्योंकि उसी हफ्ते दलाई लामा दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करने वाले थे। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुजीत दत्ता कहते हैं, "मतभेदों को बहुत सावधानी से निपटाना होगा। हमें बुनियादी समझ पैदा करनी होगी।"

विश्लेषकों का कहना है कि दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन परस्पर अविश्वास से बात बिगड़ सकती है। पत्रकार और 'चाइनीज लेशंस' के लेखक जॉन पॉमफ्रेट ने शंघाई में एक सम्मेलन में कहा, "उत्तर कोरिया–दक्षिण कोरिया के विसैन्यीकृत क्षेत्र के बाद चीन–भारत सीमा एशिया की दूसरी सबसे खतरनाक सीमा है। साल 1962 में इस सीमा पर भारत–चीन के बीच एक संक्षिप्त युद्ध भी हो चुका है जिसमें भारत पराजित हो गया था। पोमफ्रेट ने कहा, "भारत एक मात्र ऐसा देश है जिसे कम्युनिस्ट चीन युद्ध में हरा चुका है। चीन फिर ऐसा करने का प्रयास कर सकता है। इसी प्रकार भारतीय भी ऐसा करने के लिए आसानी से चीनी विरोधी लोकप्रिय उन्माद से प्रभावित हो सकते हैं। हाल में भारत–चीन के बीच गलत फहमी बढ़ी है और पोमफ्रेट एवं कई अन्य विश्लेषकों का मानना है कि यह चीनी मंत्रियों की बढ़ती स्वायत्तता की वजह से है। पहले वे एक पार्टी लाइन के आधार पर बोलते थे, लेकिन अब दिनोंदिन उनके परस्पर विरोधी बयान आ रहे हैं जिससे चीन के इरादों को समझ पाना मुश्किल हो रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज की रिसर्च फेलो रुक्मणि गुप्ता ने कहा कि चीन और भारत कई समान समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे भ्रष्टाचार, तेजी से शहरीकरण और करोड़ों गरीब लोगों का पेट भरना, लेकिन इससे निपटने का उनका तरीका अक्सर बिल्कुल अलग होता है। गुप्ता ने कहा कि जैसे भारत में भ्रष्टाचार की जड़ भारी दिखावे और राजनीति से से निकलती है, लेकिन चीन में यह कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों से पैदा होती है। शंघाई डेली अखबार के डिप्टी एडिटर झू हुआनियान ने कहा सोशल मीडिया के उभार से सरकार के लिए एक चुनौती पैदा हुई है क्योंकि अब उसकी नीतियों पर दूसरी राय बढ़ती जा रही है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के राष्ट्रवादी ब्लॉगर अक्सर सीमा एवं क्षेत्रीय विवादों पर बहुत उत्तेजित हो जाते हैं।

हिंदुस्तान टाइम्स के चौधुरी ने कहा कि एक साल पहले तक चीन भारतीय जनता के बीच जनमत सर्वे में दूसरे देशों में लगभग शीर्ष पर स्थान रखता था, लेकिन अब इसके पायदान में काफी गिरावट आई है। चौधुरी अकादमिक लोगों, पत्रकारों और थिंक टैंक विश्लेषकों के उस समूह का हिस्सा हैं जो भारत–चीन संबंधों पर गहरी नजर रखते हैं। चौधुरी ने कहा कि इसकी वजह भारतीय प्रसारण मीडिया है जो मसलों को सनसनीखेज बना देता है। भारतीय सेना के अधिकारी निजी बातचीत में यह स्वीकार करते हैं कि भारत–चीन सीमा काफी दुर्गम और अचिह्नित होने के कारण दोनों देशों के सैनिक गश्ती के दौरान अक्सर एक–दूसरे की सीमा में घुस जाते हैं।

लेकिन चौधुरी ने कहा कि चीन के भद्दे जनसंपर्क से कोई मदद नहीं मिल रही है। पिछले महीने जब एक संवाददाता सम्मेलन में एक भारतीय पत्रकार ने चीन के ब्रोशर में छपे गलत नक्शे पर सवाल उठाया तो भारत में चीनी राजदूत झांग यान ने उसे 'शटअप' (चुप रहो) कह दिया। चौधुरी ने कहा कि स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब कोई समस्या आने पर चीनी अधिकारी बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं इससे भारतीय अतिवादियों को चीन की और खराब तस्वीर पेश करने का अवसर मिल जाता है और लोगों में चीन के प्रति अविश्वास और बढ़ जाता है।

साल 1950 तक भारत की सीमा तिब्बत से लगती थी, न कि चीन से और तिब्बत पर चीन की संप्रभुता स्वीकार कर हमने चीन को सीधा अपना पड़ोसी बना लिया।

चीन के लिए सस्ते बाड़ का काम कर रहा है पाकिस्तान

विक्रम सूद

(मिडडे डॉट कॉम, 22 दिसंबर, मुंबई)

काफी परेशान सरदार पटेल ने 7 नवंबर 1950 को जवाहर लाल नेहरू को पत्र लिखकर कहा था कि संयुक्त राष्ट्र में चुप्पी साधकर हमने तिब्बत पर चीनी संप्रभुता को स्वीकार कर लिया है। एक प्रभावशाली पत्र में सरदार पटेल ने चेतावनी दी थी, "शांतिपूर्ण इरादों को दिखाते हुए चीन के सरकार ने हमें बहकाने

इस इलाके में चीन की उपस्थिति और गतिविधियां बढ़ गई हैं।

चीन समय–समय पर कई मसले खड़ा करता रहा है जैसे जम्मू–कश्मीर के निवासियों को अलग कागज पर वीजा देना या उत्तरी सैन्य कमांडर को वीजा देने से इनकार और अरुणाचल प्रदेश एवं लद्दाख में लगातार अतिक्रमण।

की कोशिश की है, लेकिन सच तो यह है कि वह एक दोस्त नहीं, बल्कि एक संभावित शत्रु है। इसके बाद उन्होंने दस ऐसे कदमों की विस्तार से जानकारी दी जो हमारी आंतरिक सीमा सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा को मजबूत करने, खासकर उत्तर–पूर्व के लिए जरूरी हैं। लेकिन दुःख की बात तो यह है कि इस पत्र पर खुलकर कभी चर्चा नहीं की गई। साल 1950 तक भारत की सीमा तिब्बत से लगती थी, न कि चीन से और तिब्बत पर चीन की संप्रभुता स्वीकार कर हमने चीन को सीधा अपना पड़ोसी बना लिया। यही नहीं हमारी इस रियायत से चीन की सीमा भूटान, नेपाल, भारत के अलावा पाक अधिकृत कश्मीर को भी छूने लगी। चीन अब दक्षिण एशिया में भी खेल करने की ताकत रखता है, जबकि माओ का चीन उपद्रवग्रस्त था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति जैसे प्रयोगों के बाद कोरियाई युद्ध शुरू हुआ। तिब्बत में 1959 में हुए विद्रोह के बाद दलाई लामा के भारत आने से चीन का व्यामोह और बढ़ गया। चीन ने सोचा कि भारत को चेतावनी देना जरूरी है और उसने मई 1959 में अपने राजूदत पान जु ली के माध्यम से प्रधानमंत्री नेहरू को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया कि चीन अब पाकिस्तान के साथ खड़ा हो सकता है। इससे भारत पर दोतरफा सैन्य और राजनय दबाव पड़ सकता था। इसमें एक ऐसे सर्वकालिक मामले की शुरुआत दिख रही थी जो समुद्र से भी गहरा और पहाड़ों से भी ऊंचा हो सकता था। इसके बाद 1962 और 1965 ऐसे ऐतिहासिक साल थे जब भारत को अपने दोनो पड़ोसियों से युद्ध करना पड़ा। इससे पाकिस्तान को चीन के और करीब जाने का मौका मिला और दोनों के बीच गर्मजोशी का रिश्ता कायम रहा। पाकिस्तान को भारतीय ताकत की बराबरी के लिए जरूरी परंपरागत हथियार, आपूर्ति तंत्र, परमाणु हथियार आदि के लिए चीन सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया इस तरह से चीन के लिए पाकिस्तान उसके दूसरे पड़ोसी भारत के खिलाफ परंपरागत बाड़ या बचाव बन गया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान में अमेरिकी दखल भी बढ़ने लगा और चीन इस बात में सुविधा महसूस करने लगा कि सस्ते और प्रभावी विदेश नीति विकल्प के तहत वहां के आतंकवादियों को सहायता दी जाए। देंग जियोपिंग के चार आधुनिकीकरण अभियान से इस नीति को और बल मिला और चीन ने न केवल अमेरिका को जवाब, बल्कि पश्चिम एशिया तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए एक सेतु के रूप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शत्रुता का इस्तेमाल किया। चीन की नजर अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों की भू–सामरिक स्थिति और वहां तेल एवं गैस, तांबा, सोना, जस्ता, सीसा, लौह अयस्क और एल्युमिनियम जैसे समृद्ध खनिज भंडारों पर थी। ऐसी भी खबरें हैं कि नाभिकीय मसलों पर चीन–पाकिस्तान–सऊदी अरब ने गठजोड़ किया है। एक चीनी अधिकारी ने एक बार एक अमेरिकी अधिकारी को बताया था कि चीन के लिए पाकिस्तान की भूमिका इजराइल की तरह है।

दूसरी तरफ, पाकिस्तान अपने लिए चीन को भारत के खिलाफ सुरक्षा के एक भरोसेमंद गारंटर के रूप में देखता है। हालांकि, सैन्य–जिहादी गठजोड़ से संचालित पाकिस्तान को यह बात समझनी चाहिए कि चीन क्षेत्रीय प्रभुत्व बनाने के लिए पाकिस्तान को एक सीढ़ी की तरह ही इस्तेमाल कर रहा है। चीन इसके अलावा पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक सस्ते, द्वितीयक धमकी के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान की प्रख्यात विश्लेषक आयशा सिद्दीक ने इस बारे में एक बहुत ही वाजिब बात रखी है। चीन एक 'चोरी से बना साम्राज्य' है जो अपने सहयोगी देशों की सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक जिम्मेदारी को अपने ऊपर लिए बिना लगातार आगे बढ़ रहा है। चीन पाकिस्तान के उन उद्योगों में ही निवेश करेगा जिसका उसे फायदा हो, न कि उसके समग्र विकास में। मकरान तट पर स्थित ग्वादर का महत्व चीन के लिए इसलिए है क्योंकि उससे उसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक बेरोकटोक जाने का रास्ता मिलता है। इस इलाके में चीन की उपस्थिति और गतिविधियां बढ़ गई हैं। दिखाने के लिए तो यह कहा जा रहा है कि चीन के कर्मियों की बढ़ती संख्या गिलगित–बाल्टिस्तान में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में काम के लिए है।

जैसे–जैसे भारत तरक्की करता जाएगा, चीन का रवैया और कठोर होता जाएगा। चीन समय–समय पर कई मसले खड़ा करता रहा है जैसे जम्मू–कश्मीर के निवासियों को अलग कागज पर वीजा देना या उत्तरी सैन्य कमांडर को वीजा देने से इनकार और अरुणाचल प्रदेश एवं लद्दाख में लगातार अतिक्रमण। चीन लगातार म्यांमार और पाकिस्तान को अपने प्रभाव में रखने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत के दोनों छोर को घेरे रखा जाए। यदि भारत ने साल 1950 में ही सरदार पटेल का सुझाव मान लिया होता तो शायद हम अपने पीछे चीन का घेरा महसूस नहीं करते और शायद पाकिस्तान आज चीन के लिए सोमालिया जैसा बन जाता न कि इजराइल जैसा।

(लेखक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख हैं।)